

उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव

वी.

डॉ. महेंद्र भास्कर लीमे और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 831)

मार्च 03,2023

[एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, विधि)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद का कार्यकाल, इस्तीफा और निष्कासन) नियम, 2020-rr. 3 (2) (ख), 4 (2) (ग), 6 (9)-मान्यता: आरआर। 3 (2) (बी), 4 (2) (सी), 6 (9) जो इसके विपरीत हैं

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय v. ऑल उत्तर प्रदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन [2016] 8 एससीआर 851 और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और एक अन्य [2020] 2 एससीआर 246 असंवैधानिक, मनमाने और Art.14 का उल्लंघन करने वाले हैं।

आरआर। 3 (2) (ख) और 4 (2) (ग) में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और 15 वर्ष का अनुभव प्रदान करने की सीमा तक

क्रमशः राज्य और जिला आयोग-केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें 2020 के नियमों में संशोधन करने के लिए-जब तक संशोधन नहीं किए जाते, उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य-एक व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है और जो क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है और जिसे उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों आदि में 10 साल से कम का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव नहीं है, उसे अध्यक्ष और राज्य और जिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा-नियुक्ति लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी जिसमें दो पेपर होते हैं।

प्रत्येक पेपर में योग्यता अंक 50 प्रतिशत होंगे और

50 अंकों की मौखिक आवाज-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 -
अधिनियम, 1986-उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति,

उपभोक्ता संरक्षण

राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला मंच के सदस्यों का वेतन, भत्ता और सेवा की शर्तें) नियम, 2017-
भारत का संविधान-Art.14,142।

उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, विधि)

भर्ती, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद का कार्यकाल, त्यागपत्र

[2023] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना और

जिला आयोग) नियम, 2020 - आर. 6 (9)-आयोजित: आर के तहत 6 (9) , चयन समिति अनियंत्रित विवेकाधिकार के साथ सशक्त है

राज्य और जिले के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति

आयोग-पारदर्शिता और चयन मानदंड अनुपस्थित हैं - जिला मंच के सदस्यों के रूप में नियुक्ति करते समय,

राज्य सरकार को 2020 के नियमों की सिफारिश नहीं की गई है उम्मीदवार की योग्यता का परीक्षण करने के लिए लिखित परीक्षा पर विचार करें।

लिखित परीक्षा जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने की थी

-

नए 2020 नियमों के तहत हटा दिया गया है-इसे समाप्त करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-उपभोक्ता

संरक्षण अधिनियम, 1986-उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, वेतन, भत्ता और राष्ट्रपति और सदस्यों की सेवा की शर्तें)

राज्य आयोग और जिला मंच) नियम, 2017।

न्यायाधिकरण-अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, सदस्यों से अपेक्षित मानक-आयोजित किए गए: आयोग अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, इसलिए, न्यायाधिकरण के सदस्यों से अपेक्षित मानक

ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जितना संभव हो उतना लागू होना चाहिए-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति की विधि)

भर्ती, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद का कार्यकाल, त्यागपत्र

और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना और

जिला आयोग) नियम, 2020-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, वेतन, भत्ता और

राष्ट्रपति और राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें

और जिला मंच) नियम, 2017।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में और

आदेश में उचित रूप से कहा गया है कि नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) के विपरीत हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय और

अन्य बनाम अखिल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसिएशन (यू. पी. सी. पी. बी. ए.)
और मद्रास बार एसोसिएशन असंवैधानिक हैं

और मनमाना। अन्यथा भी नियम 6 (9) में पारदर्शिता का अभाव है और

यह उपभोक्ता मंत्रालय V को अनियंत्रित विवेकाधिकार और अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।

डॉ. महेन्द्रभास्कर लिमये

चयन समिति। नियम 6 (9) के तहत, चयन समिति को अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है - राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करना। पारदर्शिता और चयन मानदंड नियम के तहत अनुपस्थित हैं।

6 (9) . अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता के अभाव में और योग्यता पर किसी भी मानदंड के अभाव में अयोग्य और अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्ति मिल सकती है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकती है। यह विवादित नहीं हो सकता है कि आयोगों को अदालत की शक्तियों के साथ सशक्त किया जाता है और वे अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण हैं और दीवानी और आपराधिक सहित अदालत की पर्याप्त शक्तियों के साथ न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हैं।

इसलिए, न्यायाधिकरण के सदस्यों से अपेक्षित मानकों को यथासंभव लगभग होना चाहिए।

ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियम, 2020 के नियम 6 (9) के तहत, चयन समिति के पास अधिकार है -

अपनी खुद की प्रक्रिया निर्धारित करें। इस तरह के प्रावधान चयन को अत्यधिक और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्तियां भी दे रहे हैं

समिति। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की ओर से उद्देश्य पर विचार करते हुए उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए ऐसी अनियंत्रित विवेकाधिकार शक्ति

नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश करने की प्रक्रिया

जिला और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य मनमाने और अनुचित हैं। यह हमेशा वांछनीय है कि जिला मंच और/या राज्य आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति करते समय कौशल, क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार को सूचीबद्ध और अनुशंसित किए जाने से पहले उम्मीदवारों की योग्यता। नियम, 2020 लिखित परीक्षा पर विचार नहीं करता है ताकि उम्मीदवार की योग्यता का परीक्षण किया जा सके। यू. पी. सी. पी. बी. ए. के मामले में, इस न्यायालय ने नियुक्तियों की प्रक्रिया में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की। [पैरा 6,4,6,5] [319-ई, एच; 320-ए-डी]

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और दूसरा (2021) 7 एस. सी. सी. 369: [2020] 2 एस. सी. आर. 246; उत्तर राज्य

प्रदेश और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश के सभी उपभोक्ता

प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन (2017) 1 एस. सी. सी. 444: [2016]

8 एस. सी. आर. 851-पर निर्भर।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 लिखित परीक्षा कराने के तंत्र की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई थी जिसे नए नियमों के तहत हटा दिया गया है।

2020. इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जहां तक कुछ राज्यों का संबंध है, नियम, 2017 थे और

जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, नियम, 2019, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और जिला मंचों और राज्य आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार के एकमात्र इरादे से डब्ल्यू. ई. एफ. 24.07.2020 लागू हुआ है।

काफी हद तक बढ़ाया जाता है। हालांकि, उपभोक्ता विवादों के निर्णय के संबंध में योजना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियम, 2020 तैयार करते समय लिखित परीक्षा को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है। इसलिए, जैसा कि सही है

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम, 2020 का नियम 6 (9) असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान, विशेष रूप से, जब इसके पहले के निर्णयों को ओवरराइड/ओवररूल करने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है।

अदालत और वह भी बिना किसी औचित्य के। इस न्यायालय में है उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ पूर्ण सहमति। [पैरा 6.6-6.8] [320-ई-एच; 321-ए]

1.3 नियम, 2020 के प्रावधान 4 (1) के तहत, एक व्यक्ति जो

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र (न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला) जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है, लेकिन एक जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए

सदस्य, नियम 4 (2) (सी) न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव को अनिवार्य करता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह नियम 3 (2) (बी) के तहत 20 साल का अनुभव प्रदान करना भी मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। नियम 3 (1) के तहत भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वर्तमान या पूर्व, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए योग्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, एक वकील को उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में केवल 7 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। 20 साल का अनुभव प्रदान करने की परिस्थितियों में

नियम 3 (2) (बी) के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को असंवैधानिक, मनमाना और उल्लंघनकारी माना जाता है। यह न्यायालय उपभोक्ता मंत्रालय बनाम उच्च सचिव द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है।

डॉ. महेन्द्र भास्कर लिमये

अदालत। मद्रास बार एसोसिएशन-एम. बी. ए. III के मामले में, इस न्यायालय ने विस्तृत तर्क के बाद 10 साल के अनुभव पर विचार करने का निर्देश दिया। [पैरा 7.1.7] [321-सी-एफ]

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और अन्न-एम. बी. ए.

III (2017) 7 एस. सी. सी. 369-पर निर्भर था।

1.4 विवादित में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है

उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, प्रक्रिया) के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

नियुक्ति, पदावधि, त्यागपत्र और अध्यक्ष और राज्य आयोग और जिला आयोग के सदस्यों को हटाना) नियम, 2020 को मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नियम, 2020 में संशोधन करना होगा, विशेष रूप से नियम, 2020 के नियम 6 (9) में, यह प्रावधान करते हुए कि चयन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी:

मॉडल नियम, 2017 के अनुसार नियुक्ति और

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

और जिला आयोग लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर जिसमें 100 अंकों के दो पेपर होते हैं और वाइवा वॉस के लिए 50 अंक होते हैं और लिखित परीक्षा जिसमें दो पेपर होते हैं, गणना की गई योजनाओं के अनुसार हो सकती है। केंद्र सरकार

और संबंधित राज्य सरकारों को नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) में प्रदान किए गए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के साथ-साथ जिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए 10 वर्ष का अनुभव प्रदान करने के लिए नियम, 2020 में संशोधन करना होगा, जिसे क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का अनुभव प्रदान करने की सीमा तक कम कर दिया गया है। जब तक उपभोक्ता संरक्षण में उपयुक्त संशोधन नहीं किए जाते

(नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला आयोग के सदस्य) नियम, 2020, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ण न्याय करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में और इसके बाद, एक व्यक्ति

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और जो क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा का व्यक्ति है, और विशेष [2023] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा, को राष्ट्रपति और राज्य के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा।

आयोग। इसी तरह, क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कम से कम 10 वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति या

चिकित्सा को जिला आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। यह भी निर्देशित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कि नियुक्ति के लिए

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी, जिसमें गणना की गई योजना के अनुसार दो पेपर शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर में योग्यता अंक होंगे

50 प्रतिशत होगा और 50 अंकों का वाइवा वॉयस होगा। [पैरा 8,8.1,8.3] [321-जी-एच; 322-ए-बी, एफ-एच; 323-ए-सी, जी]

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। ऑल उत्तर

प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसिएशन (2018)

7 एससीसी 423: [2018] 4 एस. सी. आर. 503-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 8 एससीआर 851

उस पर भरोसा करें

पैरा 2.6

[2020] 2 एससीआर 246

उस पर भरोसा करें

पैरा 2.6

[2018] 4 एससीआर 503

पैरा 6.2

संदर्भित किया गया है

(2017) 7 एस. सी. सी. 369

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 831

2023 .

उच्च न्यायालय के 14.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के डब्ल्यू. पी. सं. 1096 में नागपुर में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 832 और 2023 का 833।

उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये

आर. वेंकटरमानी, ए. जी., संजय जैन, ए. एस. जी., सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री चिन्मायी चंद्रा, सिद्धांत

कोहली, चितवन सिंघल, सुश्री मानसी सूद, अमरीश कुमार, सुश्री हर्षिता सुखीजा, निशंक त्रिपाठी, सुश्री तान्या अग्रवाल, अर्काज कुमार, पद्मेश मिश्रा, युवराज शर्मा, डॉ. उदय प्रकाश वारंजीकर, प्रवर्तक सुहास पाठक, सुश्री अंकिता चौधरी, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य।

अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, सुश्री आस्था शर्मा, डॉ. तुषार मंडलेकर, रविंदर सिंह, सुश्री रवीशा गुप्ता, श्रीसत्य मोहंती, संजीव कौशिक, मंटिका हरियाणानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, देवव्रत सिंह, सुश्री मुस्कान सुराना, तेजस् फड़णवीस, यतीन एम. जगतप, सुनील कुमार शर्मा, सुश्री कश्मीरा लांबाट, सुश्री किशोर लांबाट, सचिन पाहवा, वैष्णवी गुप्ता, मैसर्स। लैम्बर्ट एंड लेजिटेम, रामेश्वर प्रसाद गोयल, गगन सांघी, सुश्री अंकिता चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

गगन सांघी, सुश्री स्वाति पी. (हस्तक्षेपकर्ता)

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 14.09.2021 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2021 की जनहित याचिका संख्या 11/2021 और रिट याचिका संख्या 1096 में नागपुर की नागपुर पीठ में न्यायिक बॉम्बे, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया है और घोषणा की है

उपभोक्ता संरक्षण के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया) राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन) नियम, 2020 (इसके बाद नियम, 2020 के रूप में संदर्भित) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना, अनुचित और उल्लंघनकारी बताते हुए, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (इसके बाद अधिनियम, 2019 के रूप में संदर्भित) की धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (एन) और (डब्ल्यू) के साथ पठित धारा 29 और 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग) ने नियम, 2020 बनाए। 2.1 नियम, 2020 के नियम 3 में अध्यक्ष और राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान है। नियम 3 (2) (बी)

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न हो और वह क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो और उसे उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों में कम से कम बीस वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

2.2 नियम, 2020 के नियम 4 में राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है।

और जिला आयोग के सदस्य। नियम 4 (2) (सी) में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति

जिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो और उसे उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों में कम से कम पंद्रह वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

2.3 नियम 2020 के नियम 6 में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है।

राज्य आयोग या जिला आयोग की आवश्यकताओं और उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड को ध्यान में रखने के बाद, सत्यनिष्ठा और निर्णयात्मक अनुभव।

2.4 नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) उच्च न्यायालय के समक्ष असंवैधानिक और मनमाना होने के कारण चुनौती का विषय थे।

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। नियम 3, नियम 4 और नियम 6 निम्नानुसार हैं: -

" 3. अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ और

राज्य आयोग के सदस्य। — (1) एक व्यक्ति नहीं करेगा

राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो, जब तक कि वह नहीं है, या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं;

(2) एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

जब तक कि उसकी आयु चालीस वर्ष से कम न हो और उसके पास

(क) पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव

जिला न्यायालय या समकक्ष स्तर पर किसी भी न्यायाधिकरण या संयुक्त

जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में इस तरह की सेवा:

बशर्ते कि ऐसे सदस्यों में से पचास प्रतिशत से अधिक नहीं

नियुक्त किया जाए; या

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और

क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, और विशेष ज्ञान रखता है

और बीस वर्ष से कम का व्यावसायिक अनुभव

उपभोक्ता मामले, कानून, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, उपभोक्ता मामलों के सचिव
बनाम।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा:

जिला आयोग। — (1) एक व्यक्ति योग्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए, जब तक कि वह जिला न्यायाधीश न हो, या रहा हो, या होने के योग्य न हो।

(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

(बी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है; और (ग) क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, और विशेष ज्ञान और पंद्रह से कम का व्यावसायिक अनुभव नहीं है।

उपभोक्ता मामले, कानून, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा में वर्ष।

सरकार चयन समिति की संयोजक होगी। (3) अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी नियुक्ति केवल [2023] 4 एस. सी. आर. में किसी भी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिक्ति या अनुपस्थिति के अलावा चयन समिति

अध्यक्ष।

(4) नियुक्तियों की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा रिक्तता उत्पन्न होने से कम से कम छह महीने पहले शुरू की जाएगी।

(5) यदि किसी सदस्य के इस्तीफे या मृत्यु या नए पद के सृजन के कारण कोई पद खाली हो जाता है, तो पद खाली होने या बनाए जाने के तुरंत बाद पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(6) योग्य उम्मीदवारों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली रिक्ति का विज्ञापन प्रमुख में प्रकाशित किया जाएगा।

समाचार पत्र और राज्य के रूप में इस तरह से अन्य तरीके से प्रसारित

सरकार उचित समझ सकती है।

(7) ऐसे आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद, उनके आवेदनों के साथ योग्य उम्मीदवारों की एक सूची चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(8) चयन समिति उसे भेजे गए योग्य आवेदकों के सभी आवेदनों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझती है, तो वह उन मानदंडों के अनुसार आवेदकों को सूचीबद्ध कर सकती है जो वह तय कर सकती है।

(9) चयन समिति राज्य आयोग या जिला आयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन, सत्यनिष्ठा और न्यायिक अनुभव के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(10) चयन समिति योग्यता के क्रम में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

राज्य सरकार का विचार।

11) राज्य सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों की साख और पूर्ववृत्तियों का सत्यापन या सत्यापन कराएगी।

(12) अध्यक्ष या सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में इंगित किया गया है, जिस पर सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

(13) नियुक्ति से पहले, चयनित उम्मीदवार एक यह वचन देते हुए कि उनका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा जिससे राष्ट्रपति या सदस्य के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

2.5 उपरोक्त नियमों, अर्थात् नियम 3 (2) (बी), सी) और 6 (9) की वैधता को मूल द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

निम्नलिखित आधारों पर ईटीशनर: -

(अ)

अनियंत्रित विवेक और चयन के लिए अत्यधिक शक्ति

समिति सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी

उम्मीदवारों की नियुक्ति मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(ख) कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने से पहले उम्मीदवार की क्षमता का परीक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए,

जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा रहा है, उनके पास कानूनी योग्यता होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि.

सक्षम उम्मीदवारों की नियुक्ति के अभाव में,

(ग)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य होने की संभावना है

हताश हो जाते हैं।

(घ)

राज्य और जिले के अध्यक्ष और सदस्य

आयोग को न्यायालय की शक्तियों के साथ सशक्त किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की नियुक्ति में

(जे. एम. एफ. सी.), उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा द्वारा परीक्षण किया जाता है

और वाइवा वॉयस।

(ई)

इस माननीय न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप मॉडल नियम और

सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाने का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए,
इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के विपरीत।
पारदर्शिता और चयन मानदंड अनुपस्थित हैं

(च)

नियमों ने कहा।

(जी)

नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता का अभाव
अध्यक्ष और सदस्यों की, इस बात की प्रबल आशंका है कि

राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप।

2.6 उच्च न्यायालय के मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मामला था कि उत्तर प्रदेश राज्य और
अन्य बनाम अखिल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण [2023] 4 एस. सी. आर. के मामले में यह न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बार एसोसिएशन; (2017) 1 एस. सी. सी. 444 (इसके बाद यू. पी. सी. पी. बी. ए. के रूप में संदर्भित), ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मॉडल नियम बनाने का निर्देश दिया। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा आदर्श नियम बनाए गए और सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मामला था कि मॉडल नियमों को अपनाकर, कई राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, वेतन, भत्ता और राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला मंच के सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 2017 (इसके बाद नियम, 2017 के रूप में संदर्भित) को 18.05.2018 पर अधिसूचित किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि मॉडल नियम 2012 महाराष्ट्र राज्य में पहले से ही अस्तित्व में थे जो 03.01.2012 के तहत बनाए गए थे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 और उक्त नियम

नियम 10 के तहत जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए पहले से ही 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (इसके बाद अधिनियम, 2019 के रूप में संदर्भित) पूर्ववर्ती कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त करके 20.07.2020 से प्रभावी हुआ। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि नियम 2020 के तहत, अधिनियम, 2019 के तहत गठित जिला और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए चयन समिति को प्रदत्त शक्ति यूपीसीपीबीए (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति और जिले और राज्य के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्यों को देखते हुए

अधिनियम, 2019 के तहत गठित आयोगों का चयन लिखित परीक्षा आयोजित किए बिना किया जाता है, लेकिन केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय से इनकार किया जाता है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम अनुभव निर्धारित करना, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है; (2021) 7 एससीसी 369।

कि उसके बाद, विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) को अति-विषाणु और असंवैधानिक, अनुचित, मनमाना और मनमाना घोषित किया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और यू. पी. सी. पी. बी. ए. (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी टिप्पणियों और निर्देशों के विपरीत। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव निर्धारित करने के लिए चयन समिति को नियम 2020 के तहत पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करना।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

इसकी अपनी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो यू. पी. सी. पी. बी. ए. (ऊपर) के मामले में वर्णित की गई है और फिर से मानकों में व्यापक भिन्नताओं के साथ-साथ व्यक्तिपरक, नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बनेगी, और अंत में इसका परिणाम न्याय से इनकार होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। कि उपरोक्त प्रावधानों को असंवैधानिक, अनुचित और मनमाना ठहराते हुए, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस तथ्य पर विचार किया है कि न्यायाधिकरणों को न्यायिक कार्यों से संपन्न किया गया है और मामलों को विवेकपूर्ण तरीके से तय करने का कर्तव्य है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दी है और कहा है कि मानकों की अपेक्षा है

के लिए आवेदन किए गए न्यायाधिकरणों और मानकों के न्यायिक सदस्यों से

ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यथासंभव लगभग लागू होनी चाहिए। कि उसके बाद, मद्रास बार के मामले में इस न्यायालय के फैसलों का पालन करते हुए एसोसिएशन (सुप्रा) और यू. पी. सी. पी. बी. ए. (सुप्रा), उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है और अंतिम आदेश पारित किया है: -

आई "। 2021 की जनहित याचिका संख्या 11 की अनुमति है;

ii. रिट याचिका संख्या 1096/2021 की आंशिक रूप से अनुमति है।

iii. यह अभिनिर्धारित और घोषित किया जाता है कि 2020 के नियमों के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) मनमाने और अनुचित हैं।

और ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इसलिए रद्द कर दिया जाता है और

अलग रखें;

iv. भारत संघ को उचित प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है

नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) के विकल्प के रूप में बनाए गए नियमों को, निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, चार के भीतर असंवैधानिक घोषित किया गया। निर्णय और आदेश की तारीख से सप्ताह;

वी. द्वारा 2 फरवरी, 2021 को जारी रिक्ति सूचना

जिला आयोग के सदस्यों को इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और अलग रखें;

vi. राज्य आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, 2 तारीख की रिक्ति सूचना के अनुसरण में शुरू किए गए फरवरी, 2021, रद्द कर दिया गया है; [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

vii. राज्य के सदस्यों के चयन की नई प्रक्रिया

आयोग, अध्यक्ष और जिले के सदस्य आयोग को संशोधित नियमों के अनुसार शुरू किया जाए और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

viii. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की वैधता पर विचार नहीं किया है।

महाराष्ट्र राज्य;

ix. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

2.7 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

राज्य और जिला आयोग, या वैकल्पिक रूप से, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या नियम या दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं जो कम करेंगे नियुक्तियाँ करते समय खोज-सह-चयन समितियों के लिए उपलब्ध विवेकाधिकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चर्चा के दौरान

राज्यों के बीच यह देखा गया कि अधिकांश राज्य लिखित परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त बैठक में चर्चा के आधार पर, यह देखा गया कि एक समान नीति के रूप में न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्तियों के लिए एक लिखित परीक्षा न तो व्यवहार्य होगी और न ही वांछनीय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारणों से:

प्रति वर्ष न्यायाधिकरणों में रिक्तियों की संख्या बहुत कम है।

((i)

और कुछ न्यायाधिकरणों में केवल एकल अंकों में। आर्थिक या व्यावहारिक रूप से ऐसा करना संभव नहीं होगा।

पाँच या छह पदों के लिए परीक्षा।

, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय V. डॉ. अहिंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

अधिकांश न्यायाधिकरणों में उपभोक्ता मामलों, अर्थशास्त्र, कानून, प्रतिभूतियों, वित्त, दूरसंचार, बिजली आदि जैसे विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। एक समान पाठ्यक्रम के साथ एकल लिखित परीक्षा यह संभव नहीं होगा और किसी को विशेषज्ञता के प्रत्येक अलग-अलग क्षेत्र के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित करनी पड़ सकती है, जो पूरी प्रक्रिया को मनमाना और भारी बना देगा।

पैंतीस या चालीस या पचास से अधिक आयु के सक्षम, प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति लिखित परीक्षा लिखने और फिर अपने अंक खुले तौर पर प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को आवेदन करने से रोक सकता है जो वांछनीय हो सकते हैं।

पंद्रह या बीस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति नहीं कर सकते हैं

राज्यों में एक समान लिखित परीक्षा की आवश्यकता निर्धारित करना प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहेगा, उदाहरण के लिए, असम या गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या बहुत कम है, और कभी-कभी विज्ञापित पदों की संख्या से भी कम है। लिखित परीक्षा से रिक्त पदों को भरने में अधिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। न्यायाधिकरणों में लिखित परीक्षा की एक समान आवश्यकता निर्धारित करना भी वांछनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक न्यायाधिकरण की अपनी पात्रता मानदंड होती है और विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति उनके विचार क्षेत्र में आते हैं।

3] 4 एस. सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदाहरण के लिए, कई पदों को केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित किया जा सकता है, और इसके अधीन न्यायाधीशों के लिए यह उचित नहीं होगा

समान रूप से, बहुत कम लोग वास्तव में विशेष न्यायाधिकरणों में तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं जैसे कि टी. डी. एस. ए. टी. या ए. पी. टी. ई. एल. और इसके क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति

दूरसंचार या बिजली अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में आकर्षक करियर छोड़ने के लिए परीक्षा लिखना नहीं चाहेगी। इससे न्यायाधिकरण वांछनीय व्यक्तियों को खो देंगे, जो अन्यथा भावना में इन न्यायाधिकरणों में शामिल होना चाहते हैं

जनसेवा से।

3.1 श्री आर. वेंकटरमानी, भारत के विद्वान महान्यायवादी

उन्होंने आगे कहा है कि चयन समितियों को उनकी चयन प्रक्रियाओं के अभ्यास में मार्गदर्शन करने के लिए समान उपायों पर विचार करने के लिए भारत संघ और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक में आगे की चर्चाओं के आधार पर, यह प्रस्ताव किया गया है कि चयन समिति को उपलब्ध विवेकाधिकार का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान को नियम, 2020 के नियम 6 (9) के तहत जोड़ा जा सकता है: -

" बशर्ते कि चयन समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा जो निर्देश जारी किए जा सकते हैं,

समय-समय पर, किसी उम्मीदवार का मूल्यांकन करते समय

अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में राज्य आयोग या जिला आयोग में।

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक विकास की बात है

राज्य आयोगों और जिला आयोगों (अध्यक्ष और सदस्य) में नियुक्तियों पर लागू होने वाले समान उपाय

देशभर में पदों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, इन पदों के धारकों द्वारा किए जाने वाले वैधानिक कार्यों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपायों को तैयार किया गया है:

राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का चयन

ए।

या राज्य आयोग या जिले में सदस्य

कमीशन कुल 100 अंकों में से उसके द्वारा प्राप्त अंकों पर आधारित हो सकता है।
कुल अंक (100) हो सकते हैं
(i) साक्षात्कार के लिए 60 अंक और (ii) 40 अंकों का योग

एक उम्मीदवार की कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए।

उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

बी।

कहा गया परंतु।

अंकों के प्रस्तावित वितरण के पीछे का तर्क

सी.

इस तरह से जहाँ साक्षात्कार घटक अधिक भारी होगा

दूसरा, सबसे उपयुक्त का चयन सुनिश्चित करना है

उम्मीदवार, संलग्न पदों और कर्तव्यों के स्तर को देखते हुए

वहाँ तक।

विशेष उपलब्धियों के लिए 40 अंकों का वितरण

डी।

निम्नलिखित पर विचार किया जाए:

अंकन प्रणाली

अधिकतम

5 . मानदंड

निशानियाँ

वर्षों की संख्या 15

((i) न्यूनतम संख्या के लिए

अनुभव की बात

आवश्यक वर्षों का अनुभव

भर्ती की शर्तें-10

निशानियाँ

((ii) अतिरिक्त अनुभव के लिए

हर 2 साल में-1 अंक

(अधिकतम 5 अंक)।

2 से कम के अनुभव के मामले में

वर्षों, अनुभव के लिए अधिकतम अंक

2 वर्ष का अर्थात् 1 अंक हो सकता है
संख्या के अनुसार विभाजित
वर्षों का अनुभव। का अनुभव
छह महीने से कम समय की उपेक्षा की जा सकती
है।
इस उद्देश्य के लिए।

15

ऊँचे

(1) स्नातक के लिए-6 अंक

शैक्षिक

(ii) स्नातकोत्तर के लिए-6 अंक

(iii) पी. एच. डी. के लिए। - 3 निशानियाँ

योग्यताएँ

पूर्व सार्वजनिक

हर 4 साल की नियमित सेवा के लिए

10

प्रदान की गई सेवा

केंद्र/राज्य में या उसके अधीन प्रदान किया गया

सरकारें और संवैधानिक निकाय

- 2 अंक (अधिकतम 10 अंक)

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि समग्र विचार पर
ऐसा प्रतीत होता है कि एक लिखित परीक्षा का संचालन जो
सभी बाधाएं संभव नहीं होंगी और सबसे उपयुक्त नहीं होंगी।
चयन के उद्देश्य के लिए।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए डॉ. उदय प्रकाश वार्नजीकर
आर. तुषार मंडालेकर, विद्वान वकील की ओर से पेश हुए
उत्तरदाताओं ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों और [2023] 4 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) को मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

भारत से।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान के विवाद की हड्डी

उपभोक्ता राज्य आयोग और जिला आयोगों में उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले प्रतिवादी की उच्चतम मानकों और सख्त जांच होनी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2020 के तहत चयन विधि और अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से उपभोक्ता पर निर्णय लेने के लिए अक्षम उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।

राष्ट्रपति और राज्य के सदस्यों की नियुक्ति में प्रक्रिया और जिला आयोग। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनियंत्रित शक्तियों का ऐसा प्रत्यर्पण अवांछनीय परिणाम देगा।

4.2 उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में कि नियम 3 (2) (बी) और नियम

4 (2) (ग) और नियम, 2020 के नियम 6 (9) मनमाने, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले हैं।

इसके अंतर्गत: -

(अ)

कि नियम, 2020 के तहत चयन विधि प्रदान करती है

अनियंत्रित विवेक और चयन के लिए अत्यधिक शक्ति

समिति सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी

उम्मीदवारों की नियुक्ति मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार की योग्यता

(ख)

न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने से पहले परीक्षण की आवश्यकता है;

(ग)

सक्षम उम्मीदवारों की नियुक्ति के अभाव में,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य होने की संभावना है

हताश;

राज्य और जिले के अध्यक्ष और सदस्य

(घ)

आयोग को न्यायालय की शक्तियों के साथ सशक्त किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की नियुक्ति में, जब उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो जिला और राज्य आयोगों में नियुक्ति के लिए इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

पारदर्शिता और चयन मानदंड अनुपस्थित हैं

(ई)

नियम, 2020;

(जी)

नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता का अभाव

अध्यक्ष और सदस्यों की, इस बात की प्रबल आशंका है कि

राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विधि आयोग ने भी अपनी 272 वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि नवगठित आयोग के सदस्य

न्यायाधिकरणों के पास उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता होनी चाहिए। रिपोर्ट में नियुक्तियों में एकरूपता की भी सिफारिश की गई है।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने यू. पी. सी. पी. बी. ए. (ऊपर) के मामले में उपभोक्ता के तहत मॉडल नियम बनाने का निर्देश दिया है।

संरक्षण अधिनियम, 1986। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय द्वारा, आदर्श नियमों को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे मॉडल नियमों को अपनाकर प्रस्तुत किया जाता है, कई राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण (राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला मंच के सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) को अधिसूचित किया है। नियम, 2017 (इसके बाद नियम, 2017 के रूप में संदर्भित)। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि महाराष्ट्र राज्य ने भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.05.2019 पर मॉडल नियमों को अपनाया और मंजूरी दी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले भी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 के तहत महाराष्ट्र राज्य में मॉडल नियम 2012 पहले से ही मौजूद थे और उक्त नियमों में पहले से ही नियम 10 के तहत अध्यक्ष और जिला उपभोक्ता मंच के सदस्यों के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान था।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय ने नियुक्ति, वेतन, सेवा के लिए समान मॉडल नियमों को मंजूरी दी।

अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता विवादों के प्रभावी निर्णय के लिए शर्त आदि। उक्त मॉडल नियमों को सभी पक्षों द्वारा अपनाया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता मंचों/आयोगों की न्यायिक शक्तियां न्यायिक कार्य हैं। राष्ट्रपति और राज्य और जिला आयोग के सदस्यों के न्यायिक कार्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम, 2019) के बाद भी राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न्यायिक कार्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 20.07.2020 से लागू हुए हैं। यह

प्रस्तुत किया जाता है कि [2023] 4 एस. सी. आर. से संबंधित विधायी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2019 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों का न्यायनिर्णयन। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पूर्ववर्ती कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त करके 20.07.2020 से प्रभावी हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधानमंडल का एकमात्र उद्देश्य आधुनिक बाजार में भारी परिवर्तन और उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती असुरक्षा के कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है। अधिनियम, 2019 के तहत, जिला और राज्य आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में काफी वृद्धि की गई है। हालांकि, उपभोक्ता विवादों के निर्णय के संबंध में योजना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, उपभोक्ता आयोग अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण हैं जो दीवानी और आपराधिक सहित न्यायालय की पर्याप्त शक्तियों के साथ न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हैं।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2019 की धारा 71 के तहत, आयोगों को दीवानी अदालत की शक्तियों के साथ सशक्त किया गया है और धारा 72 के तहत आयोगों को इन शक्तियों के साथ सशक्त किया गया है -

जेएमएफसी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद जब केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, 2019 की धारा 101 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम, 2020 बनाए गए हैं, जो विवादित नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) के लिए प्रावधान करता है, तो नियमों, 2020 से पहले की स्थिति को प्रचलित से भी बदतर बना दिया। 4.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब राज्य और जिला आयोग अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहे हैं और

न्यायिक कार्य और न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग, उम्मीदवार की लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक होगा। केवल इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार से ही

इस तरह के चयन के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप और अयोग्य परिणाम प्रक्रिया।

4.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 6 (9) चयन समिति को अनियंत्रित विवेकाधिकार प्रदान करता है। में अनियंत्रित विवेक

न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिशों का मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। मद्रास बार एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में यह प्रस्तुत किया गया है कि "अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से एक ऐसे मंच द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार शामिल है जो न्यायनिर्णयन के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।" यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में नियम 6 (9) के तहत केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामलों के सचिव V को पूर्ण विवेकाधिकार दिया है।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

मानदंड और मानक निर्धारित किए बिना चयन प्रक्रिया का निर्धारण करना और यह अनुचित और मनमाना है।

4.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान भी इस आधार पर अनुचित है कि चयन समिति पर नियम, 2020 के तहत कोई नियंत्रण और शेष राशि नहीं है। चयन समिति के पास उम्मीदवारों की सिफारिशों में पूर्ण विवेकाधिकार है।

4.10 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यक्ष और आयोगों के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चार स्रोत हैं। ,

सेवारत न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, या कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास कुछ ज्ञान और अनुभव हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम चयन समिति को उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन, सत्यनिष्ठा और निर्णयात्मक अनुभव के रिकॉर्ड को ध्यान में रखने का निर्देश देते हैं। चयन समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायिक उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार कर सकती है, हालांकि,

गैर-न्यायिक स्रोतों से आने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण समग्र क्षमता का परीक्षण किए बिना नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वाग्रह और पारदर्शिता के बिना नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देंगी।

4.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2020 इस प्रकार यू. पी. सी. पी. बी. ए. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को रद्द कर देते हैं।

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। ; (2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 463) ने रिट याचिका (सी) संख्या 502/2021 में निर्णय लिया कि इस देश में विधायी ओवरराइड की अनुमति इस न्यायालय द्वारा निर्णय के कैटेना में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए जो निम्नानुसार हैं: -

" 44. इस देश में विधायी ओवरराइड की अनुमति इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।
उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णयों में, जिनके पास है

इसे निम्नानुसार निकाला गया है:

क) न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून

पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी संशोधन होना चाहिए

उचित और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ख) मान्यता देने वाले विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष की ओर इशारा करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि मान्यता देने वाले कानून द्वारा लाए जाने की मांग की गई परिवर्तित स्थिति न्यायालय के समक्ष मौजूद होती।

अपना निर्णय देना। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि निर्णय का आधार

दोष को इंगित करना हटा दिया जाता है।

ग) एक अधिनियम द्वारा परमादेश को समाप्त करना अनुज्ञेय विधायी अभ्यास होगा [देखिए: एस. आर. भागवत (ऊपर)]। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है।

[देखिए: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (ऊपर) और चिकित्सा

भारतीय परिषद बनाम। केरल राज्य।

घ) संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और घुसपैठ

विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में प्रवेश करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत का संविधान "।

4.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होने का मानदंड भी नियम 3 (2) (बी) के तहत राज्य आयोग और अनुभव होने के मानदंड

नियम 4 (2) (सी) के अनुसार जिला आयोग में सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 15 वर्ष का प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और अवैध और असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 233 के प्रावधानों के विपरीत है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी मद्रास बार एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का उल्लंघन है।

4.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने जिले में सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए एक वकील के लिए 15 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता के रूप में नियम 4 (2) (सी) के प्रावधान को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

फोरम/कमीशन मनमाना और अवैध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार भी एक वकील

उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में केवल सात साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नियम 4 (1) के प्रावधानों के अनुसार भी एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र है (जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव है) जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में

नियुक्त होने का योग्य है। लेकिन नियुक्त होने के लिए सदस्य, धारा 4 (2) (सी) न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव को अनिवार्य करती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

4.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि योजना की परिकल्पना की गई है

राज्य के राष्ट्रपति के लिए नियम 3 (1) के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति

आयोग के अलग मानदंड हैं और नियम 3 (2) (बी) के तहत सदस्य का मानदंड अलग और विशिष्ट है। व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकता है यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तथापि, राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए नियम 3 (2) (बी) न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य करता है, जो अवैध और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक वकील की योग्यता और अनुभव की आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार केवल दस वर्ष है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उच्च न्यायालय ने सही घोषित किया है कि नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) अति-विषाणु, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए उच्च न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर चर्चा और विचार किया है: (2021) 7 एससीसी 369।

4.16 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त पर भरोसा करना

निर्णय लेने पर, वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. श्री आर. वेंकटरमानी, विद्वान महान्यायवादी

भारत, अपीलार्थी (ओं) और डॉ. उदय प्रकाश वारंजीकर और डॉ. तुषार मंडालेकर की ओर से पेश होते हुए, संबंधित प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

6. विवादित फैसले और आदेश से उच्च न्यायालय ने

घोषित नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और उपभोक्ता संरक्षण के नियम 6 (9) (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि,

नियुक्ति की प्रक्रिया, पद का कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया

राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला आयोग के सदस्य) नियम, 2020 को असंवैधानिक, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) जिन्हें असंवैधानिक घोषित किया गया है, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता है: -

" 3. अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ और

राज्य आयोग के सदस्य।

XXX

(2) एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

जब तक कि उसकी आयु चालीस वर्ष से कम न हो और उसके पास

4 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, और विशेष ज्ञान रखता है और बीस वर्ष से कम का व्यावसायिक अनुभव

उपभोक्ता मामले, कानून, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी,

सार्वजनिक स्वास्थ्य या दवा:

जिला आयोग। — (1) एक व्यक्ति योग्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए, जब तक कि वह है, या रहा है, या योग्य नहीं है

जिला न्यायाधीश बनना।

(2) एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

जब तक कि वह

XXX

(ग) क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला और विशेष क्षमता रखने वाला व्यक्ति है।

पंद्रह से कम का ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव

उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन में वर्ष,

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग,

प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा।

XXX

6. नियुक्ति की प्रक्रिया।

XXX

(9) चयन समिति अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश करना

राज्य आयोग या जिला आयोग और लेने के बाद

उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड, अखंडता को ध्यान में रखते हुए

और न्यायिक अनुभव।

XXX

6.1 विवादित निर्णय की शुद्धता पर विचार करते हुए

नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) के नियम, इस न्यायालय के पूर्व निर्णय, विशेष रूप से, यू. पी. सी. पी. बी. ए. (ऊपर) जो उपभोक्ता संरक्षण 1986 के तहत था, को संदर्भित करने की आवश्यकता है। गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता के संबंध में मुद्दा यू. पी. सी. पी. बी. ए. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा था।

यह उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.] इससे पहले गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों सहित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरिजीत बट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि मंच का गठन निम्नानुसार किया गया है -

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उतना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करता है जितना कि

एक खराब संगठनात्मक व्यवस्था के कारण सी. टी. डी.; पूरी तरह से अपर्याप्त संरचना; पर्याप्त और प्रशिक्षित श्रमशक्ति की अनुपस्थिति और न्यायनिर्णायक निकायों में "नियुक्त सदस्यों की कमी"। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में उल्लेख किया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 4. राज्य और जिला स्तर पर पीठासीन सदस्यों, विशेष रूप से गैर-न्यायिक सदस्यों की गुणवत्ता खराब है। इसका एक कारण यह है कि उपभोक्ता के गैर-न्यायिक सदस्यों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है, वह राज्य से राज्य में भिन्न होता है और योग्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बहुत कम है। अधिकांश गैर-न्यायिक सदस्य छोटे-छोटे आदेश लिखने या निर्देशित करने में भी सक्षम नहीं हैं। कुछ स्थानों पर

गैर-न्यायिक सदस्य पीठासीन अधिकारी के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करते हैं, जबकि कानून के विपरीत आदेश पारित करते हैं, जिससे न्यायनिर्णायक निकाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। नतीजतन, राष्ट्रपति ऐसी स्थिति को पसंद करते हैं जहां ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य काम से अनुपस्थित रहते हैं यदि केवल इसलिए कि न्यायिक कार्य पीठासीन न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से किया जा सके। कई गैर-न्यायिक सदस्य समय का पालन नहीं करते हैं और अन्य सप्ताह में एक या दो बार छिटपुट रूप से काम पर जाते हैं। समिति ने पाया है कि

समस्या इस बात में निहित है-(i) उचित पारिश्रमिक का अभाव; (ii) पूर्व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति जिनमें प्रेरणा की कमी है और उत्साह; (iii) जिला मंचों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में वकालत करने वाले वकीलों की नियुक्ति; और (iv) नियुक्तियों में राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप। गैर-न्यायिक सदस्यों में से कई भाग लेते हैं

कार्यस्थल केवल उन आदेशों पर हस्ताक्षर करने के लिए है जिनका मसौदा तैयार किया गया है

पीठासीन अधिकारी।

5. समिति ने ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे

नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव ने चयन को प्रभावित किया है।

एक प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मंचों का कार्यकरण है

समिति ने स्थिति का एक स्पष्ट उदाहरण दिया: " (15) समिति यह पता लगा सकती है कि इसमें काफी नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव/हस्तक्षेप रहा है।

उपभोक्ता मंचों की "चयन प्रक्रिया" और कार्यप्रणाली।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए समिति ने पाया कि राजनेताओं, नौकरशाहों और न्यायिक बिरादरी के रिश्तेदारों का चयन किया गया है। जिला फोरम, मेरठ में तैनात एक गैर-न्यायिक सदस्य श्री जमाल अख्तर 11-5-2015 के बाद से बिना अनुमति के अनुपस्थित हैं।

राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है।

अनसुना। परिणाम यह है कि उनका पद खाली घोषित नहीं किया गया है और एक अन्य गैर-न्यायिक सदस्य को कहीं और तैनात किया गया है। उसके स्थान पर संलग्न।

(16) एक गैर-न्यायिक सदस्य जिनका पहला कार्यकाल था

लखनऊ और अब अपने दूसरे कार्यकाल का आनंद ले रही है,

जिला फोरम, बाराबंकी के लिए नियुक्त किया गया है लेकिन किया गया है

ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ और रिपोर्टों के अनुसार, सप्ताह में एक या दो बार फोरम में आता है। एक अन्य महिला गैर-न्यायिक सदस्य जो

एक नौकरशाह की पत्नी को जिले के लिए नियुक्त किया गया था

जिला उपभोक्ता मंच प्रभावित होता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कम होता है राष्ट्रपति का मनोबल।

(17) हरियाणा में, एक गैर-न्यायिक महिला सदस्य ने किया/करती है

जिला फोरम में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन लगभग 150/160 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। एक जिला मंच के अध्यक्ष जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, वे अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं। ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य प्रबंधन करते हैं

चयनित होना और फिर सदस्यों के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना,

वे खुद को "न्यायाधीश" कहते हैं।

6. पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के रूप में व्यक्तियों का चयन चयन के लिए एक निश्चित मानदंड के बिना मंचों में पारदर्शिता का अभाव है। समिति ने, हमारे विचार में, औचित्य के साथ, प्रस्ताव दिया है कि

ज्ञान का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए वे व्यक्ति जो जिला मंच में पदों के लिए आवेदन करते हैं। टकराव के मुद्दे

रुचि तब भी उत्पन्न होती है जब स्थानीय क्षेत्र से व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं।

उन्हें उसी क्षेत्र में एक जिला मंच में नियुक्त किया जाता है।

अंततः पैराग्राफ 28 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित जारी किया:

नियम:

- उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V. डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

" 28.1 . संघ सरकार इस उद्देश्य के लिए

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10 (3) और धारा 16 (2) के तहत नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करना, राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल नियम तैयार करना। मॉडल नियम चार महीने के भीतर बनाए जाएंगे और अनुमोदन के लिए इस न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

28.2 . केंद्र सरकार चार महीने के भीतर कार्यान्वयन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करने वाले मॉडल नियम भी बनाएगी।

जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की क्रमशः नियुक्ति के संबंध में धारा 10 (1) (बी), धारा 16 (1) (बी) और धारा 20 (1) (बी) के प्रावधान;

28.3 . केंद्र सरकार मॉडल नियम बनाते समय इसके लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के निर्माण का उचित ध्यान रखेगी।

ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों में निर्दिष्ट क्षेत्र क्षेत्रों में संबंधित मंचों के सदस्यों के पास होने के लिए आवश्यक क्षमता, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन। मॉडल नियम वेतन के भुगतान के लिए प्रावधान करेंगे, न्यायनिर्णायक कर्तव्यों की प्रकृति और न्यायनिर्णायक निकायों में उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता के अनुरूप भत्ते और उपभोक्ता मंच के सदस्यों की सेवा की शर्तों के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष के साथ उचित परामर्श के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

आयोग, ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर;

28.4 . इस न्यायालय द्वारा मॉडल नियमों की मंजूरी के बाद, राज्य सरकारें मॉडल नियमों को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगी -

नियम बनाने की शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त नियम बनाना।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 के तहत;

28.5 . राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण

आयोग से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय आयोग में निहित प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए आज से तीन महीने की अवधि के भीतर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ धारा 30-ए के तहत नियम बनाए।

धारा 24-बी (1) (3) के तहत राज्य आयोगों पर और राज्य आयोगों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में

उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस निर्णय में वर्णित धारा 24-बी (2) के संदर्भ में जिला मंचों पर

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ". [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.2 उसके बाद, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अखिल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण बार के एक और आदेश के माध्यम से

एसोसिएशन-सिविल अपील सं. 2740/2007 (2018) 7 एस. सी. सी. 423 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा बनाए गए प्रारूप मॉडल नियमों पर विचार किया। इस न्यायालय के समक्ष आदर्श नियमों को न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा स्वीकार किया जाने लगा। इसलिए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें भारत संघ द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा मॉडल नियमों के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित नियम बनाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद कई राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण (राष्ट्रपति और राज्य आयोग और जिला मंच के सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 को अधिसूचित किया। नियम, 2017, जिन्हें अपनाया गया था, में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक मामले में, सदस्यों का चयन

जिला मंच और राज्य आयोग दो पेपरों (नियम 5 और 7) की लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य ने भी 200 अंकों की लिखित परीक्षा वाले 24.05.2019 और बनाए गए नियम, 2019 पर मॉडल नियमों को अपनाया और उन्हें मंजूरी दी। इसने प्रावधान किया कि राज्य आयोग सदस्यों के पद के लिए 250 अंकों की अंतिम परीक्षा आयोजित करेगा। 250 अंकों में से 200 अंक लिखित परीक्षा के लिए और 50 अंक मौखिक परीक्षा के लिए होंगे। मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) के मामले में निर्णय लिया गया कि 27.11.2020 (2017) 7 एस. सी. सी. 369, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों पर विचार करते हुए

उक्त निर्णय इस न्यायालय ने विधायी की अनुमति पर भी विचार किया ओवरराइड करें। विधायी अधिमान्यता पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने कहा और कहा कि

पैराग्राफ 42 से 44 निम्नानुसार है: -

" 42. मदन मोहन पाठक बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ (1978) 2 एस. सी. सी. 50 की गहन जांच की आवश्यकता है क्योंकि इसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव के जीवन को निर्देशित करने के लिए एक आदेश दिया गया था।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

बीमा निगम (एल. आई. सी.) दिनांकित 24.01.1974 के निपटान की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा जिसे दिनांकित 29.03.1974 के प्रशासनिक निर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ एल. आई. सी. द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) को प्राथमिकता दी गई थी। एल. पी. ए. के लंबित रहने के दौरान एल. आई. सी. (निपटान संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू हुआ। एल. पी. ए. को बाद के कानून को देखते हुए वापस ले लिया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अंतिम हो गया। एल. आई. सी. के कर्मचारियों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में उक्त कानून की वैधता पर हमला किया गया था। न्यायमूर्ति भगवती, बहुमत की ओर से बोलते हुए, यह राय रखते थे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय केवल एक घोषणात्मक निर्णय नहीं था जिसमें एक ढोंग या कर को अमान्य माना गया था ताकि एक मान्य कानून निर्णय में बताए गए दोष को दूर कर सके। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावी बनाया और एल. आई. सी. को वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया। जब तक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलट नहीं दिया जाता है

अपील, इसकी उपेक्षा या उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एल. आई. सी. को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पत्र द्वारा बाध्य माना गया था। न्यायमूर्ति बेग ने अपनी समवर्ती राय में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए अधिदेश के आधार पर कर्मचारियों को प्राप्त अधिकारों को बाद के कानून द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद, मदन मोहन

पाठक (सुप्रा) श्री रंगा मैच में चर्चा के लिए आए उद्योग बनाम। भारत संघ 1994 पूरक (2)
एस. सी. सी. 726। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की राय थी कि मदन मोहन पाठक

मामले को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि

मैंडमस को विधायी अधिनियम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति हंसारिया इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। ए. वी. नचाने बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। भारत संघ (1982) 1 एस. सी. सी. 205, न्यायमूर्ति हंसारिया ने अभिनिर्धारित किया कि मदन मोहन पाठक मामले में न्यायमूर्ति बेग द्वारा लिए गए कानूनी रुख को बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ था और यही कारण था कि ए. वी. नचाने में आरोपित प्रासंगिक नियम को दी गई पूर्वव्यापीता ने रिट के प्रभाव को रद्द कर दिया था और तदनुसार अमान्य था। मतभेद को देखते हुए, मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। हमें झुका हुआ न्यायमित्र सूचित करता है कि मतभेद का समाधान नहीं किया जा सका क्योंकि मामला अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. विरेन्द्र सिंह हुड्डा (2004) 12 एस. सी. सी. 588 के मामले में इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के उस तर्क को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि पूर्वव्यापी विधान द्वारा अधिकारों को नहीं खोया जा सकता है। हालांकि, यह देखा गया कि ऐसे अधिकारों को छीनना होगा

यदि अनुच्छेद 14, 16 या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होता है तो यह अनुज्ञेय नहीं है। पहले से की गई नियुक्तियाँ

इस न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को इस कारण से संरक्षित किया गया था कि "कानून विधायिका को अदालत के निर्णय के कार्यान्वयन में जो दिया गया है उसे छीनने की अनुमति नहीं देता है।

निर्णय लें। इस तरह का पाठ्यक्रम अस्वीकार्य है "। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96 (2) में इस न्यायालय ने उस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें सांविधिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की गई थी क्योंकि यह एक व्यक्तिगत निर्णय को पक्ष में रखता है और इसलिए, न्यायिक शक्ति के विधायी प्रयोग के बराबर है। जब मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश को एक कानून द्वारा रद्द करने की मांग की गई थी, तो इस न्यायालय ने एस. आर. भागवत बनाम में इसे रद्द कर दिया। मैसूर राज्य (1995) 6 एस. सी. सी. 16 इस आधार पर कि यह अस्वीकार्य विधायी अभ्यास था। निर्णय में बताए गए दोष को हटाए बिना न्यायालय के किसी निर्णय को शून्य पर स्थापित करना मृत्यु प्रतीत होगा।

कानून के शासन का गला घोटना। कानून के शासन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि तब सरकार के लिए यह खुला रहेगा कि वह किसी कानून की अवहेलना करे और फिर भी उससे बच जाए। 50 44. इस देश में विधायी ओवरराइड की अनुमति इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, जिन्हें नीचे दिया गया है:

क) न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए। और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

ख) एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष की ओर इशारा करने वाला निर्णय नहीं होता पारित किया गया, यदि न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय वैधीकरण कानून द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति मौजूद थी। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष में उपभोक्ता मंत्रालय का सचिव V होना चाहिए।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

इस तरह से ठीक किया गया है कि निर्णय का आधार इंगित करता है

ग) एक अधिनियम द्वारा मैडमस का उन्मूलन होगा -
अस्वीकार्य विधायी अभ्यास [देखू: एस. आर. भागवत (ऊपर)]। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी
वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है।

[देखिए: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (ऊपर) और भारतीय चिकित्सा परिषद v. केरल राज्य (2019) 13 एस. सी. सी. 185]

घ) संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और संविधान में घुसपैठ

विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति के सिद्धांत का उल्लंघन है

शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन और संविधान के अनुच्छेद 14

भारत का संविधान "।

[illegible]

भारत और एन. आर. - एम. बी. ए. III-(2017) 7 एस. सी. सी. 369 ने 27.11.2020 पर निर्णय लिया, जो एक अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड से निराश है।

6.4 उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, उच्च

न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में उचित रूप से कहा है कि नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) जो यू. पी. सी. पी. बी. ए. के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों के विपरीत हैं।

(ऊपर) और मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) असंवैधानिक और मनमाने हैं।

6.5 अन्यथा भी हमारी राय है कि नियम 6 (9) में पारदर्शिता का अभाव है और यह अनियंत्रित विवेक और अत्यधिक विवेक प्रदान करता है।

चयन समिति को शक्ति। नियम 6 (9) के तहत, चयन

समिति को राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। नियम 6 (9) के तहत पारदर्शिता और चयन मानदंड अनुपस्थित हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के मामले में पारदर्शिता के अभाव में और योग्यता पर किसी भी मानदंड के अभाव में अयोग्य और अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्ति मिल सकती है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि

आयोगों को अदालत की शक्तियों के साथ सशक्त किया जाता है और वे अर्ध [2023] 4 एस. सी. आर. होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक प्राधिकारी और दीवानी और आपराधिक सहित न्यायालय की पर्याप्त शक्तियों के साथ न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करने के लिए सशक्त। इसलिए,

न्यायाधिकरण के सदस्यों से अपेक्षित मानक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यथासंभव लगभग लागू होने चाहिए। नियम, 2020 के नियम 6 (9) के तहत, चयन समिति के पास अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति है। इस तरह के प्रावधान चयन समिति को अत्यधिक और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्तियां भी दे रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की ओर से उद्देश्य पर विचार करते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, जिला और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की अनियंत्रित विवेकाधिकार मनमाना और अनुचित है। यह हमेशा वांछनीय है कि जिला मंच और/या राज्य आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति करते समय उम्मीदवारों के कौशल, क्षमता और योग्यता का आकलन करने की आवश्यकता होती है।

राज्य सरकार को सूचीबद्ध और अनुशंसित किया गया। नियम, 2020 लिखित परीक्षा पर विचार नहीं करता है ताकि उम्मीदवार की योग्यता का परीक्षण किया जा सके। यू. पी. सी. पी. बी. ए. (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने प्रक्रिया में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की

नियुक्तियाँ।

6.6 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि तंत्र

इस न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा की पुष्टि की गई थी जिसे नए नियम, 2020 के तहत हटा दिया गया है।

6.7 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत, जहां तक कुछ राज्यों का संबंध है, नियम, 2017 और जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, नियम, 2019 थे, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान था

और वाइवा वॉयस, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत था।

6.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और जिला मंचों और राज्य आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ाने के एकमात्र इरादे से डब्ल्यू. ई. एफ. 1 से लागू हुआ है। हालांकि, उपभोक्ता विवादों के निर्णय के संबंध में योजना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियम, 2020 तैयार करते समय लिखित परीक्षा को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, नियम, 2020 का नियम 6 (9) असंवैधानिक, मनमाना और उपभोक्ता मंत्रालय बनाम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

डॉ. महेंद्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

भारत का संविधान, विशेष रूप से, जब इस न्यायालय के पहले के निर्णयों को ओवरराइड/ओवररूल करने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है और वह भी बिना किसी औचित्य के। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

7. अब जहां तक नियम, 2020 के नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को सही ही रद्द कर दिया है

जिसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव प्रदान किया गया है नियम 3 (2) (बी) के तहत राज्य आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति और नियम 4 (2) (सी) के तहत जिला आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 15 साल का अनुभव होना।

7.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि नियम, 2020 के प्रावधान 4 (1) के तहत, एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र है (न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव) जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है, लेकिन सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए, धारा 4 (2) (सी) न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य करती है जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है।

7.2 इसी तरह नियम 3 (2) (बी) के तहत 20 साल का अनुभव प्रदान करना भी मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है।

संविधान। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 3 (2) (बी) के तहत, 10 साल का अनुभव रखने वाला न्यायालय का पीठासीन अधिकारी राज्य आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र है। धारा 3 (1) के तहत भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वर्तमान या पूर्व, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए योग्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, एक वकील को उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में केवल 7 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों के तहत 20 साल का अनुभव प्रदान करने के लिए

नियम 3 (2) (बी) को असंवैधानिक, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। हम पूर्ण हैं

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सहमति। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मद्रास बार एसोसिएशन (उपरोक्त)-एम. बी. ए. III के मामले में, इस न्यायालय ने विस्तृत तर्क के बाद 10 साल के अनुभव पर विचार करने का निर्देश दिया।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम देखते हैं

उपभोक्ता संरक्षण के नियम 3 (2) (बी), नियम 4 (2) (सी) और नियम 6 (9) को घोषित करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और निष्कासन) नियम, 2020 को मनमाना, अनुचित और (2023) 4 एस. सी. आर. का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नियम, 2020 में संशोधन करना होगा, विशेष रूप से नियम, 2020 के नियम 6 (9) में, यह प्रावधान करते हुए कि चयन समिति नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का पालन करेगी।

मॉडल

नियम, 2017 और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जिसमें 100 अंकों के दो पेपर और वाइवा वॉस के लिए 50 अंक होते हैं और लिखित परीक्षा जिसमें दो पेपर होते हैं, निम्नलिखित योजनाओं के अनुसार हो सकती है: -

मैक्स।

अवधि

विषय-वस्तु

परीक्षण की प्रकृति

कागज

निशानियाँ

(क) सामान्य ज्ञान और उद्देश्य प्रकार 100

2 घंटे

पेपर-I

समसामयिक मामले

(ख) संविधान का ज्ञान

भारत का

((C) विभिन्न विषयों का ज्ञान

उपभोक्ता संबंधित कानून

अनुसूची में दर्शाया गया है

(क) वर्णनात्मक 100 विषयों पर एक निबंध

3 घंटे

पेपर-II

व्यापार प्रकार के मुद्दों में से चुना गया

संबंधित मुद्दे या सार्वजनिक

मामले।

विश्लेषण और ठोस क्षमताएँ

आदेशों का प्रारूपण।

8.1 केंद्र सरकार और संबंधित राज्य

सरकारों को नियम, 2020 में भी संशोधन करना होगा ताकि राज्य आयोग के साथ-साथ जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष का अनुभव प्रदान किया जा सके।

नियम 3 (2) (बी) और नियम 4 (2) (सी) को क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का अनुभव प्रदान करने की सीमा तक निरस्त कर दिया गया है। तब तक

उपभोक्ता संरक्षण (योग्यता) में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। नियुक्ति, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद का कार्यकाल, त्यागपत्र और राष्ट्रपति और राज्य के सदस्यों को हटाने के लिए

आयोग और जिला आयोग) नियम, 2020, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ण न्याय करने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में और इसके बाद, एक व्यक्ति जिसके पास स्नातक है उपभोक्ता मंत्रालय V.

डॉ. महेन्द्र भास्कर लिमये [एम. आर. शाह, जे.]

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और जो क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा का व्यक्ति हो, और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त में कम से कम 10 वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो।

जिला आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा को योग्य माना जाएगा। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह भी निर्देश देते हैं कि राष्ट्रपति और राज्य के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आयोग और जिला आयोग, नियुक्ति लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी जिसमें दो पेपर शामिल होंगे।

निम्नलिखित योजना: -

कागज

विषय-वस्तु

परीक्षण मैक्स की प्रकृति।

अवधि

निशानियाँ

(क) सामान्य ज्ञान और उद्देश्य प्रकार

2 घंटे

पेपर-I

समसामयिक मामले

(ख) संविधान का ज्ञान

भारत का

((C) विभिन्न विषयों का ज्ञान

उपभोक्ता संबंधित कानून

अनुसूची में दर्शाया गया है

(क) विषयों पर एक निबंध

वर्णनात्मक

पेपर-II

3 घंटे

और व्यापार

व्यापार प्रकार के मुद्दों में से चुना गया

उपभोक्ता

संबंधित मुद्दे या सार्वजनिक

मामले।

((b) एक मामले का अध्ययन

परीक्षण के लिए उपभोक्ता मामला

विश्लेषण और ठोस क्षमताएँ

आदेशों का प्रारूपण।

8.3 प्रत्येक पेपर में योग्यता अंक 50 प्रतिशत होंगे और

50 अंकों का वाइवा वॉयस होगा। इसलिए, 250 में से अंक आवंटित किए जाएंगे, जिसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें दो पेपर होंगे।

100 अंकों का और वाइवा वॉस के आधार पर 50 अंकों का।

वर्तमान अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे (अभिषेक अग्निहोत्री और शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)